

दैनिक लोकतंत्र की शान

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दिल्ली से प्रकाशित

सोमवार 25 मई 2026

लोकतंत्र का स्तंभ

प्रधानमंत्री ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का लेख किया साझा सिक्किम की सांस्कृतिक विरासत और विकास मॉडल को सराहा

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए राज्य की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास मॉडल की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में कंचनजंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना का संरक्षक बताया गया है, जो राज्य के 'विकसित सिक्किम-2047' के विजन को दिशा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा कि सिक्किम अपने राज्यत्व के 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंचनजंगा की पांच धरोहरों के माध्यम से राज्य की पहचान, परंपरा और विकास यात्रा को प्रभावाशली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ये पांच धरोहरें 'विकसित सिक्किम-2047' की दिशा में राज्य की प्रगति को प्रकाशित कर रही हैं। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित अपने लेख में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिक्किम को सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास का आदर्श उदाहरण बताया। उन्होंने लिखा कि राज्य का विकास केवल आधारभूत संरचना तक सीमित नहीं है,



बल्कि यह जनता के विश्वास, प्रकृति के संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ा है। सिंधिया ने अपने लेख में कंचनजंगा को सिक्किम की आत्मा करार देते हुए कहा कि हिमालय की गोद में स्थित यह पर्वत केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि राज्य की सामूहिक चेतना, आस्था और परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने कंचनजंगा से जुड़ी पांच धरोहरों सोना, चांदी, रत्न, अन्न और पवित्र ग्रंथ का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है, जहां विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का अनूठा मॉडल देखने को मिलता है। सिंधिया ने राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खेती और टिकाऊ पर्यटन को भविष्य

के विकास की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि सिक्किम में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। सड़क, डिजिटल संपर्क और पर्यटन अवसरचना के विस्तार के बावजूद पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का निरंतर प्रयास किया गया है। लेख में सिक्किम की सांस्कृतिक विविधता, बौद्ध धर्म, स्थानीय परंपराओं और सामाजिक समरसता की भी विस्तार से चर्चा की गई है। सिंधिया ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में सिक्किम हरित विकास, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और सतत पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है। उन्होंने कहा कि सिक्किम की विकास यात्रा आधुनिकता और परंपरा के संतुलन का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है।

इबोला पर केंद्र सरकार का देशवासियों को परामर्श, कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने से बचें

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इबोला प्रभावित देशों में बदलती स्थिति को देखते हुए और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशों के अनुरूप सभी भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। कांगो, युगांडा और उसकी सीमा से लगे दक्षिण सूडान और अन्य देशों में बीमारी फैलने सबसे अधिक खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार भारतीय नागरिक जो वर्तमान में इन देशों में रह रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल निर्देशों का सख्ती से पालन करें और अतिरिक्त सावधानी बरतें। डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन समिति ने 22 मई को आगमन के प्रवेश बिंदुओं पर बीमारी की निगरानी को मजबूत करने के लिए कुछ अस्थायी सिफारिशें जारी की हैं। इन सिफारिशों में 'बुंदिबुगुयो वायरस पाए जाने वाले क्षेत्रों की यात्रा न करने'

की भी सलाह दी गई है। भारत में बुंदिबुगुयो वायरस स्ट्रेन के कारण होने वाली इबोला बीमारी का अबतक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इबोला रोग एक वायरल हेमोरेजिक बुखार है, जो इबोला वायरस के 'बुंदिबुगुयो' स्ट्रेन के संक्रमण के कारण होता है। यह एक गंभीर बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक है। वर्तमान में बुंदिबुगुयो स्ट्रेन के कारण होने वाले इबोला रोग की रोकथाम या उपचार के लिए किसी भी टीके या विशिष्ट उपचार को मंजूरी नहीं दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के तहत 17 मई को इस स्थिति को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया था। अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा को प्रभावित करने वाले बुंदिबुगुयो स्ट्रेन इबोला वायरस रोग के मौजूदा प्रकोप को आधिकारिक तौर पर 'महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया है।

ज्वलंत मुद्दा संपादकीय अधिकारों का अहंकार लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा



भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा माना जाता है। 1950 में लागू हुए संविधान ने देश के नागरिकों को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के साथ ही न्याय की गारंटी दी है। संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में ऐसी त्रिस्तरीय व्यवस्था तैयार की, जिसका उद्देश्य शक्ति का संतुलन बनाए रखना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन वर्तमान समय में यह प्रश्न गंभीरता से उठने लगा है कि क्या ये संस्थाएं अपने मूल दायित्वों का निर्वाह उसी निष्पक्षता और संवेदनशीलता से कर रही हैं, जिसकी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। जब नागरिक अपने मताधिकार से सरकार चुनते हैं, तो वे केवल सत्ता नहीं सौंपते, बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य की रक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य को देते हैं। संविधान ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी संस्था निरंकुश न हो। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन्हें लागू करेगी और न्यायपालिका इस बात की निगरानी करेगी कि संविधान और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा मजबूत होती दिखाई दे रही है कि सत्ता और अधिकार का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। सरकारें कठोर कानून बना रही हैं, जांच एजेंसियां लंबे समय तक लोगों को जेलों में बंद रख रही हैं और अदालतों में न्याय मिलने में असामान्य देरी हो रही है। इससे नागरिकों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या न्याय केवल कागजों तक सीमित होकर रह गया है।

भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है, "जमानत नियम है और जेल अपवाद।" इसके बावजूद आज न्याय मामलों में आरोपी वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में बंद रहते हैं। कई बार मुकदमे शुरू तक नहीं हो पाते, जबकि आरोपी अपनी संपादित सजा से अधिक समय जेल में बिता देता है। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक संकट में धकेल देती है। चिंता की बात यह है कि कठोर कानूनों के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था जरूरी हैं, लेकिन इनके नाम पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं मानी जा सकती। जब कानून का प्रयोग समान रूप से न होकर चयनात्मक रूप से होता दिखाई देता है, तब नागरिकों का विश्वास कमजोर होने लगता है।

सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL.SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

साक्षिप्त समाचार

हमारे 94 फीसदी से ज्यादा फॉलोअर्स और दर्शक भारत से ही हैं: दिपके

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने इस प्लेटफॉर्म को मिलने वाले समर्थन के पीछे पाकिस्तान और अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का हाथ होने का इशारा किया है। इसके बाद पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस पर फटकार किया है। बता दें रिजजू ने इस डिजिटल आंदोलन पर तीखा हमला बोला था। रिजजू ने लिखा- मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस गैंग से अपने फॉलोअर्स तलाशते हैं। भारत के पास अपनी परंपरा आबादी और अत्यधिक ऊर्जावान युवा हैं, जो वास्तविक और मूल्यवान फॉलोअर्स बन सकते हैं। भारत विरोधी गैंग से सत्यापन लेने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक्स पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की। अभिजीत दिपके ने दावा किया कि यह उनके आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दर्शकों का डेमोग्राफिक डेटा है, जिसे उनका अकाउंट हैक होने से पहले मीडिया के साथ भी साझा किया गया था। दिपके ने रिजजू को टैग करते हुए लिखा- डेटा के मुताबिक हमारे 94 फीसदी से ज्यादा फॉलोअर्स और दर्शक भारत से ही हैं। आखिर एक केंद्रीय मंत्री भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी का टैग क्यों दे रहे हैं? यह डिजिटल आंदोलन महज एक हफ्ते के अंदर देश के सबसे बड़े सोशल मीडिया पेजों में से एक बन गया है।

वटोटा में रेलवे ट्रैक पर धमाका, 23 की मौत, 30 घायल

वटोटा। पाकिस्तान के वटोटा शहर में एक बड़ा और भीषण बम धमाका हुआ है, जिसमें भारी संख्या में जान-माल के नुकसान की खबर है। शुरुआती स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जोरदार धमाका वटोटा में फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के गेट के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर हुआ। विस्फोट उस समय हुआ जब ट्रेक की तरफ से आ रही एक ट्रेन वहां से गुजर रही थी। धमाका इतना शक्तिशाली था कि ट्रेन की एक बोगी के परखच्चे उड़ गए, कई डिब्बे पटरी से उतर गए और रेलवे ट्रैक के आसपास के इलाके में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार, इस दिल दहला देने वाले हादसे में कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सभी घायलों को इलाज के लिए वटोटा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। धमाके के बाद आसमान में धुएं का भयंकर गुबार देखा गया और रेलवे ट्रैक के पास खड़े कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। यह हादसा वटोटा के मन फाटक इलाके में पेश आया है। यह आत्मघाती हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने वटोटा का दौरा किया था और वहां तैनात टुकड़ियों के अधिकारियों व सैनिकों से बातचीत कर सुरक्षा माहौल की समीक्षा की थी। सेना के इस दौरे के बीच ही उग्रवादियों ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है।

कांग्रेस गांधीवादी मूल्यों के बजाय गालियों वाली पार्टी बन गई है: पूनावाला

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं से बैठक में एक ऐसी बात कह दी, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं को अपने समुदाय से जुड़े मुद्दों को मुखबरा से उठाने और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, कि अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो उन्हें केवल 'अल्पसंख्यक' समूह के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि विशेष रूप से एक 'मुसलमान' के रूप में अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि अगर दलितों, ओबीसी या सामान्य वर्ग के सदस्यों पर हमले होते हैं तो



उस विशिष्ट समुदाय की स्पष्ट रूप से पहचान करके इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने जिस तरह से मुसलमानों के संदर्भ अपनी बात रखी उस पर राजनीति गरमा गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के इस कमेंट से कांग्रेस और उनके नेता के भाव और चिंतन का पता चलता है। इससे ये भी साफ होता है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है।

सर्वर डाउन के चलते सीबीएसई रि-इवैल्युएशन के आवेदन नहीं कर पा रहे स्टूडेंट

नई दिल्ली। सीबीएसई ने 19 मई से ऑनर-शंट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन तकनीकी खामियों से वेबसाइट पिछले पांच दिनों से लगातार क्रैश हो रही है। आज आवेदन की आखिरी तारीख है, लेकिन वेबसाइट लोड ही नहीं हो पा रही। अगर साइट खुल भी जाए, तो एक स्टैप बढ़ने के लिए पेज को कम से कम 10 बार फ्रेश करना पड़ रहा है। जिन छात्रों ने 3-4 दिन पहले आवेदन किया था, उन्हें न तो अभी तक कॉपी मिली है और न ही मेल या टेक्स्ट के जरिए कोई जानकारी। सर्वर डाउन, पेमेंट फेल होने और धुंधले पन्नों जैसी तकनीकी दिक्कतों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लिया है। उन्होंने बोर्ड से जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ छात्रों को सुबह 11:30 बजे पेमेंट सफल होने और एप्लीकेशन सबमिट होने का मैसेज मिला, शाम 6:45 बजे अचानक मैसेज आया कि उनके पैसे रिफंड कर दिए गए हैं और आवेदन सबमिट ही नहीं हुआ। स्टूडेंट्स इस बात से परेशान हैं कि अगर सफल पर कॉपी नहीं मिली, तो वे अपनी कॉपीयों के री-इवैल्युएशन के लिए समय पर आवेदन कैसे कर पाएंगे।

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने से कोई नहीं रोक सकता

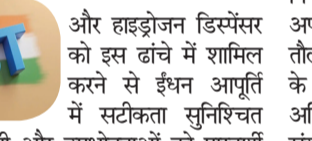
अहिल्यानगर। महाराष्ट्र के शिर्डी में रक्षा मंत्री राजनथ सिंह ने शनिवार को एनआईबीई गुप की रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भारत कभी हथियारों का आयातक था, उसे अगले 25-30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 50फीसदी तक बढ़ाना चाहती है। राजनथ सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ पूरी फेक्ट्री का निरीक्षण किया और भारत के पहले 300 किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम 'सूर्यस' को रहीं झंडी दिखाई। बाद में दोनों नेताओं

केंद्र का पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन के डिस्पेंसर की जांच और पुनः सत्यापन व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला

एजेंसी। नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसर (इंधन भरने की मशीनों) की जांच और पुनः सत्यापन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लीगल मेट्रोलाजी नियमों में संशोधन कर इन इंधन डिस्पेंसर को सरकार से अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) व्यवस्था के दायरे में शामिल किया है। इससे इंधन माप प्रणाली की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक विवरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग ने लीगल मेट्रोलाजी (सरकार से

जीएटीसी के दायरे में लाया गया

अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, संशोधन के तहत अब पेट्रोल-डीजल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों की जांच तथा पुनः सत्यापन भी जीएटीसी के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके साथ ही जीएटीसी के तहत सत्यापन योग्य उपकरणों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। सरकार ने कहा कि देश में स्वच्छ इंधनों के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सीएनजी, एलएनजी



और हाइड्रोजन डिस्पेंसर को इस ढांचे में शामिल करने से इंधन आपूर्ति में सटीकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के अनुसार, सरकार से अनुमोदित परीक्षण केंद्र ऐसे संस्थान हैं, जिनके पास माप एवं तौल उपकरणों की जांच और पुनः सत्यापन के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और आधारभूत संरचना उपलब्ध होती है। निजी प्रयोगशालाओं और उद्योगों की भागीदारी से देश की

कैलिफोर्निया में केमिकल टैंक लीक, 40 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा

एजेंसी। कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में केमिकल टैंक लीक हो गया। एयरोस्पेस फैक्ट्री में रक्षा केमिकल टैंक रूकुरवान में रखा जा रहा था। इसके बाद आसपास के करीब 40 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। कई स्कूल बंद कर दिए गए और राहत शिविर खोले गए हैं। कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी स्थित गार्डेन ग्राव शहर की है। यहां जिक्रेपन एयरोस्पेस नाम की कंपनी में मिथाइल मेथाक्रिलेट नाम का रसायन रखने वाला प्रेशराइज्ड टैंक गम हो गया और उससे जहरीली गैस लीक हो गई। ऑरेंज काउंटी फायर अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक टैंक फट

कई स्कूल किए बंद, घटना में किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं



सकता है या उसमें दरार आ सकती है, जिससे जहरीला केमिकल जमीन पर फैल सकता है। मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि टैंक में करीब 22,700 से 26,500 लीटर प्लास्टिक कंटेनरों वाला खतरनाक केमिकल मिथाइल

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 25 मई को मिजोरम में 32.15 करोड़ की मत्स्य परियोजनाओं का करेगे उद्घाटन-शिलान्यास

एजेंसी। नई दिल्ली। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 25 मई को मिजोरम में 32.15 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण मत्स्य पालन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र में आधुनिक, टिकाऊ और आत्मनिर्भर मत्स्य पालन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्रालय के अनुसार आइजोल में 'क्षेत्रीय समीक्षा बैठक : पूर्वांचल क्षेत्र-2026' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजीव रंजन सिंह मंत्री 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएसएसवाई) और मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसरचना विकास कोष

(एफआईडीएफ) के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह क्षेत्र पूर्वांचल राज्यों में मत्स्य पालन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आजीविका के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री क्षेत्र के मत्स्य पालन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इनमें मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), सर्वश्रेष्ठ मत्स्य पालन स्टार्टअप तथा उच्च मत्स्य सहकारी समितियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभागों

के मंत्री, विभागीय सचिव और केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना है। साथ ही किसानों के कल्याण, सतत क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों (एमडीसीएस) के विस्तार के लिए ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण की शुरुआत, अफ्रीकी स्वाइन फीवर जागरूकता फिल्म का विमोचन, 'सुराज पालन' अर्थात् पशुपालन पद्धतियों पुस्तिका का लोकार्पण तथा मिजोरम मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड द्वारा मुलकों गाय के धी की लॉन्चिंग शामिल है।

एक बार फिर व्हाइट हाउस के बाहर अंधाधुंध गोलीबारी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा चौकी पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। वहां तैनात सिक्रेट सर्विस के एजेंटों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमलावर को गोली मारकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस घटना में हमलावर समेत दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जांच के अनुसार, हमलावर मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है, हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक उसकी आधिकारिक पहचान और हमले के कारणों का खुलासा नहीं किया है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना व्हाइट हाउस के पास स्थित 17वें स्ट्रीट और पेनसिलवैनिया अवेन्यू के सुरक्षा जांच केंद्र पर हुई। एक सतिद्विध व्यक्ति अचानक चौकी की तरफ बढ़ा और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाकर्मीयों की गोली लगने से वह वहीं गिर पड़ा। इस घटना की पुष्टि करते हुए एफबीआई डायरेक्टर कारा पटेल ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर चुकी हैं।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

उप्र. मदरसा बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का दबदबा, 29 हजार से ज्यादा छात्राएं पास

लोकतंत्र की शान , लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आयोजित मदरसा शिक्षा परिषद के वर्ष 2026 की परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। इस वर्ष 29 हजार से अधिक छात्राएं पास हुई हैं। जिनका सफलता प्रतिशत 94.30 प्रतिशत रहा है। छात्राओं ने टॉप रैंकिंग में भी अपना दबदबा कायम किया है। यह उपलब्धि केवल छात्राओं की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों और पारदर्शी व्यवस्था का भी सकारात्मक असर है।

29 हजार से अधिक छात्राएं हुईं पास-उप्र. मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा वर्ष 2026 की मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) परीक्षा में कुल 55,788 छात्र-छात्राएं सफल हुए हैं, जिनमें 29,229 छात्राएं शामिल हैं। छात्राओं का कुल सफलता प्रतिशत 94.30 रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में बेटियों को बेहतर शैक्षिक माहौल और अवसर मिल रहे हैं। सेकेंडरी (मुंशी/मौलवी) परीक्षा में 21,407 छात्राएं पास हुई हैं। जिनका सफलता प्रतिशत 91.46 रहा है। वहीं सीनियर सेकेंडरी (आलिम) परीक्षा में 7,822 छात्राओं ने सफलता हासिल की, जिसका सफलता प्रतिशत 90.88 दर्ज किया गया है।

यमुनानगर: बिजली संकट पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, आधी रात को पावर हाउस का घेराव

लोकतंत्र की शान , यमुनानगर। धोषण गमी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार देर रात यमुनानगर के व्यासपुर स्थित बिजली पावर हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पावर हाउस का घेराव कर बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की और आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग उठाई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। ग्रामीणों के अनुसार कपरी, मारवा तथा आसपास के गांवों में पिछले कई दिनों से अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात विभिन्न गांवों के लोग व्यासपुर पावर हाउस पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इसी प्रकार मिर्जापुर क्षेत्र में भी ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि पहले सीमित समय के लिए कट लगाए जाते थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से स्थिति अधिक खराब हो गई है। दिनभर काम के बाद रात में भी बार-बार बिजली बाधित होने से लोगों की नींद और दिनचर्या प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि तेज गर्मी में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है। कई परिवारों के पास वैकल्पिक बिजली व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों को पूरी रात जागकर बितानी पड़ रही है। धरने की सूचना मिलने पर बिजली निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकारियों ने उच्च स्तर पर समस्याएं उठाने तथा अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होने देने का आश्वासन दिया। निगम के एक्सईएन द्वारा आपूर्ति व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

अमृतसर में गोली लगने से तीन साल के बच्चे की मौत, दादी घायल

लोकतंत्र की शान , चंडीगढ़। पंजाब के अमृतसर स्थित छेहरटा क्षेत्र में शनिवार देर रात हुए हादसे में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसकी दादी घायल हो गई। पुलिस के अनुसार छेहरटा क्षेत्र निवासी साजन बच्चों को स्कूल में पीटीएम के लिए गया था। उसके पास लाइसेंस वाली पिस्तौल भी थी। घर लौटने के बाद उसने कपड़े बदलते समय लोडेड पिस्तौल बेल्ट पर रख दी। इसी दौरान खेलते-खेलते तीन साल के मासूम वंश ने पिस्तौल उठा ली और अचानक ट्रिगर दब गया। गोली बच्चे के आर-पार निकल गई और पास खड़ी उसकी दादी को भी जा लगी। परिजन तुरंत बच्चे और घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने वंश को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वंश जुड़वा भाई था और उसकी अचानक मौत से परिवार पूरी तरह टूट चुका है। सूचना मिलने पर पंजाब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना छेहरटा के एसएचओ बलविंदर सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना का लग रहा है। पुलिस के मुताबिक पिस्तौल अनलॉक हालत में थी, जिसके कारण बच्चा आसानी से उसे उठा सका।

कपूरथला जेल में भिड़े कैदी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति संभाली

झगड़े के दौरान जेल में दहशत फैलाने के लिए कई स्थानों पर आग भी लगाई गई

लोकतंत्र की शान , चंडीगढ़। पंजाब के कपूरथला की केंद्रीय जेल में बैरक बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। शनिवार की देर रात यहां कैदियों के दो गुटों में शुरू हुई झड़प रातभर चलती रही। कुछ घंटे तक कैदियों ने पूरी जेल को अपने कब्जे में रखा और भीतर से वीडियो जारी कर रहे। झगड़े के दौरान जेल में दहशत फैलाने के लिए कई स्थानों पर आग भी लगाई गई। रविवार अल सुबह तक सभी कैदियों को बैरकों में बंद करके स्थिति को नियंत्रित किया गया। जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने कहा कि कपूरथला जेल की बैरक नंबर चार में बीती रात कैदियों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। करीब 100 से 150 कैदी अपनी बैरकों से बाहर आ गए। उन्होंने हंगामा किया और बैरक नंबर 4 में आग लगा दी। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि कैदियों ने चढ़ा तैनात सुरक्षा कर्मियों को खदेड़ दिया और एक-दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। कुछ कैदियों ने जेल में पड़े कचरे के ढेरों को आग लगानी शुरू कर दी। कुछ कैदी मशाल लेकर जेल की छत पर चढ़ गए और वीडियो बनाकर वायरल करने लगे। यहां की बैरक नंबर चार को भी आग के हवाले कर दिया गया।

नूद में अगस्त में सजेगा राजपूती संस्कृति का रंगारंग महाकुंभ

तीन दिवसीय 'चांपावत बाईसा स्नेह मिलन समारोह' की तैयारियां शुरू

लोकतंत्र की शान

मेड़ता रोड , एजाज अहमद उस्मानी। राजपूत समाज की ओर से आयोजित होने वाला बहुप्रतीक्षित 'चांपावत बाईसा स्नेह मिलन समारोह' इस वर्ष 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को नूद में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। समारोह को लेकर समाज बंधुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रविवार को आयोजित समाज की बैठक में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हुए विभिन्न कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में तय किया गया कि यह तीन दिवसीय आयोजन राजपूती परंपरा, संस्कृति, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का अनूठा उदाहरण बनेगा। समारोह में महिलाओं के लिए लाल एवं पीली राजपूती पोशाक का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, जबकि पुरुष संफेद कुर्ता-पायजामा के साथ मारवाड़ी शान के प्रतीक इशारिया साफा धारण करेंगे। समारोह के दौरान नूद गढ़ से चामुण्डा माता मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा में



पारंपरिक वेशभूषा में सजे समाज बंधु बैड-बाजों और ढोल-नगाड़ों के साथ शामिल होंगे। चामुण्डा माता के दर्शन के बाद आयोजन स्थल पर परिचय सम्मेलन, पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं राजपूती सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें समाज की गौरवशाली विरासत की झलक देखने को मिलेगी। बैठक में प्रशासक महेंद्र दुर्गा सिंह राठौड़ सहित समाज के कई गणमान्य सिंह, पप्पू सिंह, इब्बर सिंह, भानु प्रताप सिंह, तेजपाल सिंह, श्याम प्रताप सिंह, मूल सिंह, धूड़ सिंह, समद्र सिंह, भगवान सिंह, देवी सिंह, मदन सिंह, प्रेम सिंह, सज्जन सिंह, गोपाल सिंह, सरदार सिंह, महावीर सिंह, अमर सिंह, करण सिंह, राजू सिंह, हरि सिंह, किशन सिंह, विजय सिंह, मनोहर सिंह, रणवीर सिंह, गुलाब सिंह, श्रवण सिंह एवं दुर्गा सिंह राठौड़ सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुल्डोजर

सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण
चुरहट एसडीएम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

(श्रद्धा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के चुरहट क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुल्डोजर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया। एसडीएम चुरहट विकास कुमार आनंद स्वयं मौके पर पहुंचे और पुलिस बल तथा राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सलैया स्थित शासकीय आराजी खसरा क्रमांक 47, कुल रकबा 0.050 हेक्टेयर में से 0.010 हेक्टेयर भूमि पर राजारान तिवारी पिता गिरवधारी तिवारी निवासी सलैया द्वारा बाड़ कब्जा किया गया था। मामले की



जानकारी मिलने के बाद पटवारी हल्का सलैया द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण को अतिक्रमणकारी की नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। नोटिस के बाद अनावेदक उपस्थित तो हुआ, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वहीं प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यह प्रमाणित हुआ कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके बाद एसडीएम विकास

कुमार आनंद ने आदेश जारी करते हुए अतिक्रमणकारी पर 1000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया और सरकारी भूमि से बेदखल करने के निर्देश दिए। आदेश के पालन में प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया। एसडीएम स्वयं पुलिस बल, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कराई। कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि पर की गई बाड़ को हटाया गया और जमीन को पुनः शासन के कब्जे में लिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। स्थानीय लोगों ने भी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई को सराहा। इनका कहना है। शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कुमार आनंद, एसडीएम चुरहट।

दुआरा खदान में प्रशासन का बड़ा एक्शन

संदिग्ध ब्लास्टिंग और विस्फोटक गड़बड़ी पर छापा, खदान संचालन तत्काल बंद

(श्रद्धा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के बहरी तहसील अंतगत ग्राम दुआरा स्थित पथर खदान में अनियमितताओं और संदिग्ध विस्फोटक उपयोग की शिकायत पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त छापामार अभियान चलाया। कलेक्टर विकास मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देश पर प्रशासनिक और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आई। जांच के दौरान खदान क्षेत्र में सीमा चिह्न, तार फेंसिंग और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं पाए गए। प्रशासन ने इसे जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए तत्काल प्रभाव से खदान में



उत्खनन और ब्लास्टिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी। कार्रवाई के दौरान विस्फोटक कार्य में प्रयुक्त वाहन क्रमांक MP17G-3415 भी मौके पर मिला। वाहन में मौजूद लोगों से विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उपयोग में गंभीर अनियमितता माना है। प्रशासन ने वाहन को थाना बहरी के सुपुर्द कर विस्फोटक अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा से खिलवाड़ और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जबलपुर-पुणे एवं जबलपुर-बांद्रा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के नियमित संचालन का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल अंतर्गत आज दिनांक 24 मई 2026 को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जबलपुर-पुणे (ट्रेन संख्या 20162/20161) एवं जबलपुर-बांद्रा (ट्रेन संख्या 20164/20163) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के नियमित संचालन के शुभारंभ अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं रेलवे अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग के माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक, माननीय लोकसभा सांसद आशीष दुबे, विधायक पाटन अजय विरनाई, विधायक



कैट अशोक रोहाणी, विधायक बरगी नीरज सिंह लोधी, विधायक सिहोरा संतोष वरकड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रेलवे प्रशासन की ओर से मंडल रेल प्रबंधक श्री कमल कुमार ततरेजा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री आनंद कुमार एवं श्री दिनेश कुमार कलामे, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री शशांक गुप्ता सहित अन्य शाखा अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में

कसिहवा हादसे के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ शासन-प्रशासन



(श्रद्धा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। ग्राम कसिहवा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहायता का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार मृत बच्चों के परिजनों को 6-6 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने कार्यक्रम निरस्त कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सहायता राशि के चेक सौंपे। सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक रीती पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी परिवार को सांत्वना देते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने परिवार के पुनर्वास, आवास निर्माण और जीवित बची बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही गांव में पेयजल और बिजली सुरक्षा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए हैं।

समाज सेवा में सक्रिय युवाओं को मिला सम्मान

एडवोकेट तेज सिंह रूवा बने प्रदेश विधि सलाहकार

अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान की युवा कार्यकारिणी का विस्तार, संगठन ने जताया भरोसा

लोकतंत्र की शान

नागौर/मेड़ता रोड , एजाज अहमद उस्मानी। समाज हित एवं संगठनात्मक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाने वाले नागौर जिले के डेगाना निवासी एडवोकेट तेज सिंह रूवा को अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान की प्रदेश युवा कार्यकारिणी में प्रदेश विधि सलाहकार नियुक्त किया गया है। संगठन की ओर से की गई इस नियुक्ति के बाद समाजजनों, युवाओं एवं विभिन्न पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है। समाजबंधुओं ने तेज सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए इसे पूरे समाज के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। संस्थान के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने कार्यकारिणी विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन समाज में एकता, शिक्षा, सामाजिक

समाज सेवा में सक्रिय युवाओं को मिला सम्मान

एडवोकेट तेज सिंह रूवा बने प्रदेश विधि सलाहकार

अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान की युवा कार्यकारिणी का विस्तार, संगठन ने जताया भरोसा

लोकतंत्र की शान

नागौर/मेड़ता रोड , एजाज अहमद उस्मानी। समाज हित एवं संगठनात्मक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभाने वाले नागौर जिले के डेगाना निवासी एडवोकेट तेज सिंह रूवा को अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान की प्रदेश युवा कार्यकारिणी में प्रदेश विधि सलाहकार नियुक्त किया गया है। संगठन की ओर से की गई इस नियुक्ति के बाद समाजजनों, युवाओं एवं विभिन्न पदाधिकारियों में हर्ष का माहौल है। समाजबंधुओं ने तेज सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए इसे पूरे समाज के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। संस्थान के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने कार्यकारिणी विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन समाज में एकता, शिक्षा, सामाजिक



जागरूकता एवं युवा नेतृत्व को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रहा है। इसी क्रम में संगठन के प्रति समर्पण, सामाजिक सरोकारों में सक्रियता तथा विधिक मामलों की बेहतर समझ को देखते हुए एडवोकेट तेज सिंह रूवा को प्रदेश

विधि सलाहकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि तेज सिंह लंबे समय से समाज हित से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से कार्य करते आ रहे हैं। युवाओं के बीच उनकी सकारात्मक सोच, मिलनसार व्यक्तित्व एवं सामाजिक भागीदारी के कारण उनकी अलग पहचान बनी हुई है। संगठन को विश्वास है कि उनके अनुभव, कानूनी ज्ञान एवं मार्गदर्शन से समाज संगठन को नई दिशा एवं मजबूती मिलेगी। साथ ही समाज से जुड़े विभिन्न कानूनी विषयों एवं सामाजिक मामलों में भी संगठन को लाभ प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारी मिलने पर एडवोकेट तेज सिंह रूवा ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व एवं समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जिस विश्वास के साथ उन्हें यह दायित्व सौंपा है, वे उसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज हित सर्वोपरि है तथा युवाओं को संगठित कर समाज सेवा के कार्यों को और अधिक गति देने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठजनों, युवाओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एडवोकेट तेज सिंह रूवा को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान में सात दिन से लापता जापानी पर्वतारोही का शव मिला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तरी गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके में सात दिन से लापता जापान के बुजुर्ग पर्वतारोही का शव मिल गया है। एक स्थानीय पर्वतारोहण क्लब के स्वयंसेवकों के सहयोग से चलाए बचाव अभियान के दौरान जापान के पर्वतारोही का शव खोजने में सफलता मिली। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 64 वर्षीय योसुके अकिबा गिलगित-बाल्टिस्तान के स्कादू जिले में मसरूर रॉक व्यू पॉइंट पर गए थे। यह जगह समुद्र तल से 3,700 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर है। इस स्थान सिंधु नदी और आसपास के पहाड़ों के मनमोहक नजारे दिखाई देते हैं। रेस्क्यू 1122 सेवा के प्रवक्ता गुलाम रसूल ने मीडिया को बताया कि अकिबा का शव चट्टान के पास ह्रस्वनाद इलाके में एक गहरी दरार में मिला। वह वहां बिना किसी स्थानीय ट्रिस्ट गार्ड के मदद से गए थे। रसूल ने बताया कि शव को रिसियों और खास उपकरणों की मदद से बाहर निकाला गया और अब उसे नीचे स्कादू लाया जा रहा है। सदपारा पर्वतारोहण क्लब के स्वयंसेवकों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। क्लब के चेयरमैन गुलाम मुहम्मद सदपारा ने बताया कि क्लब के चार अनुभवी पर्वतारोहियों ने रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर इस अभियान में हिस्सा लिया।

नेपाल-चीन के बीच सीमा सुरक्षा समन्वय पर बैठक में उठा केरूंग क्षेत्र का मुद्दा

काठमांडू। नेपाल और चीन के बीच नियमित सीमा समन्वय बैठक रसुवा जिले के धुन्चे स्थित जिला प्रशासन कार्यालय में रविवार को हुई है। नेपाल की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी राजेश पन्थी और चीन के अधिकारियों का का नेतृत्व चु जिनशुन ने किया। बैठक में केरूंग क्षेत्र का मुद्दा उठा। अधिकारियों के अनुसार बैठक में सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने, व्यापार सुगम करने, आपसी समन्वय बढ़ाने, सीमा पार अपराध नियंत्रण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कहा गया है कि यह बैठक नेपाल और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैश्वीकरण संबंध, आपसी विश्वास और सहयोग को और मजबूत करने में उपयोगी रही। दोनों पक्षों ने हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्र



में रहने वाले लोगों के लिए व्यापार, यातायात और दैनिक जीवन को आसान बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेपाल ने केरूंग क्षेत्र में कार्पेट नेपाली नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र में अवैध व्यापार और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी-अपनी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और निगरानी बढ़ाने पर सहमति जताई। रसुवा जिले के बाहर के नेपाली ड्राइवरों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रवेश की अनुमति देने के विषय पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। चीन के अधिकारियों ने संकेत दिया कि पासपोर्ट रखने वाले और अच्छे आचरण रिपोर्ट वाले ड्राइवरों को चरणबद्ध तरीके से प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। इस कदम का नेपाली परिवहन व्यवसायियों और कारोबारी समुदाय ने स्वागत किया है। अधिकारियों के अनुसार, चीन की पहले की उस नीति में नरमी आने की उम्मीद है, जिसमें केवल रसुवा जिले के ड्राइवरों को प्राथमिकता दी जाती थी। इससे व्यापार और यातायात गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई गई है।

एनएमडीसी ने दक्षिण बस्तर के 17 गांवों में लगाया समर कैंप, 1700 बच्चे लेंगे भाग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने दक्षिण बस्तर के दंतवाड़ा जिले में जनजातीय समुदायों के बच्चों के लिए 17 गांवों में समर कैंप शुरू किया है। यह कैंप 20 मई से शुरू किया गया है, जो 15 जून तक चलेगा। केंद्रीय स्पात मंत्रालय के अनुसार इस पहल के तहत करीब 1700 बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अनुभवात्मक शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों और खेलों से जोड़ा जाएगा। अधिकांश गांवों में गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, जबकि बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वर्तमान में प्रत्येक गांव में प्रतिदिन 30 से 40 बच्चे कैंप में भाग ले रहे हैं। कैंप में बच्चे प्रतिदिन तीन से चार घंटे तक पठन-पाठन, शिल्पकला और संगीत कार्यशालाओं में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद फ्रिसबी, कबड्डी और खो-खो जैसे खेल आयोजित किए जा रहे हैं। दिन का समापन पौष्टिक अल्पाहार के साथ किया जा रहा है। एनएमडीसी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक शिक्षा के अक्सर सीमित होने के कारण यह पहल बच्चों की प्रतिभा और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी। कंपनी की ओर से इसे गांवों के समग्र विकास और वंचित समुदायों के बच्चों में सामाजिक एवं आत्मविश्वास से जुड़ी क्षमताओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। समर कैंप में बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इस पहल का और विस्तार किया जाएगा।

अलीगढ़: तकनीकी खराबी आने पर विमान को खेत में उतारा, पायलट और प्रशिक्षु छात्र सुरक्षित

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के धनीपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले एक प्रशिक्षु विमान में अचानक तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने प्युशुबुझ से विमान को खेत में उतार दिया। पायलट और प्रशिक्षु छात्र दोनों सुरक्षित हैं। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। एडीएम सिटी अतुल गुप्ता ने बताया कि रविवार सुबह आठ बजकर 25 मिनट पर पायलट ने प्रशिक्षु छात्र के साथ उड़ान भरी थी। विमान तकनीकन एक घंटे तक आसमान में उड़ा फिर अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने विमान को थाना हरदुआगंज क्षेत्र के चंगेरी गांव के पास खेत में उतार दिखा। उसमें पायलट और प्रशिक्षु छात्र दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। विमान को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एडीएम सिटी ने बताया कि ट्रेनी एयक्राफ्ट (बीटी-पीएफबी) ने धनीपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। आसमान में पहुंचते ही विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। तुरंत उसकी लैंडिंग अलीगढ़ के एक खेत में कराई गई। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।

मप्र के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले से महिला की मौत, 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का ऐलान

भोपाल। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा रेंज क्षेत्र में शनिवार की रात एक बाघ ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हार्दसे पर दुख व्यक्त कर मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उमरिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा रेंज के ग्राम खेरवा टोला निवासी महिला फूल भाई पाल (48) पत्नी पहलू पाल शनिवार-रविवार की दरमियानी रात अपने घर में सो रही थी। रात करीब तीन बजे बाघ ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाघ के हमले में दशईया पाल समेत चार लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद काफी देर तक महिला का शव घर के अंदर पड़ा रहा और बाघ आसपास ही मौजूद था। ग्रामीणों की सूचना पर रविवार सुबह वन विभाग की टीम गांव पहुंची, जिसके बाद घायलों की अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर इंदवार पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में बाघ की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। गुस्ताफ ग्रामीणों ने पनपथा रेंजर प्रतीक श्रीवास्तव के साथ मारपीट कर दी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और सिर पर भी चोट लगी है। किसी तरह उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। इसी दौरान महिला रेंजर अंजु वर्मा को भी ग्रामीणों ने घेरे लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की व मारपीट की गई। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेत्री एवं जनपद सदस्य रोशनी सिंह धुर्वे मौके पर पहुंचीं।

आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जी जान से जुटें कार्यकर्ता: मायावती

एजेंसी, लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने रविवार को यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता कोई कसरन छोड़े और पूरे जी जान से वोट की सुरक्षा करें।



बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को यहां 12 माल एक्वेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कोआर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक की। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई-नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी की तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त-दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की जरूरत है। ताकि पार्टी के पक्ष में बढ़ते हुए जन रुझान के फलस्वरूप

कारण फिर जनता अपने आपको काफी ठगा हुआ महसूस करने लगती है, किंतु उसका क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत। बसपा प्रमुख ने कहा कि पार्टियां चुनाव के समय जनहितैषी और जनकल्याणकारी होने का डिंडोरा पीटती है और उससे धन लुटाती है। चुनाव खत्म होने के बाद अपने वादों, घोषणाओं अन्य दावों आदि के प्रति उदासीनता और लापरवाह क्यों हो जाती है। यही कारण है कि इन पार्टियों की छलावापूर्ण एवं विभाजनकारी राजनीति से देश व जनहित का सही से भला नहीं हो पा रहा है। उनका जीवन लगातार लाचार और मजबूर बना हुआ है। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद महंगाई, बेरोजगारी, नये-नये नियम और कानून आदि के जरिए हर प्रकार के तनाव समेत उनके जीवन के जंजाल को और भी बढ़ा दिया जाता है। जिससे आज करोड़ों की जनता को इज्जत और सम्मान के साथ जीना मुश्किल हो गया है।

कंचनगंगा में हिमस्खलन, कोई नुकसान नहीं, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

एजेंसी, दमोली

उत्तराखंड के चमोली जिले के बदरीनाथ यात्रा के दौरान कंचनगंगा क्षेत्र में हिमस्खलन की घटना सामने आई है। घटना के दौरान आसपास मौजूद यात्रियों और स्थानीय लोगों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि अथवा संकट का नुकसान नहीं हुआ है और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।



लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और यात्रा व्यवस्थाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने आमजन से सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें। जानकारी के अनुसार, बढ़ते तापमान के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे हिमखंडों के टूटने और नीचे खिसकने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

कमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार ने रविवार को बताया कि हिमस्खलन सड़क तक नहीं पहुंचा और खाई क्षेत्र में ही रुक गया, जिससे यातायात एवं आम जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और पर्वतीय क्षेत्रों में समय-समय पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी है और संबंधित विभाग

टिवशा शर्मा मौत मामला : दिल्ली एम्स की टीम ने किया दोबारा पोस्टमॉर्टम

एजेंसी, भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभिनेत्री और मॉडल टिवशा शर्मा के शव का रविवार को दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय टीम ने दोबारा पोस्टमॉर्टम किया। भोपाल के दोबारा पोस्टमॉर्टम करीब 3 घंटे तक चला। इस दौरान भोपाल एम्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। एम्स परिसर की मॉंच्युरी के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा। दिल्ली एम्स से आई मेडिकल टीम ने शनिवार को टिवशा शर्मा के शव का भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमॉर्टम किया। करीब तीन घंटे तक चली पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्यवाही की गई। मॉंच्युरी में आवश्यक दस्तावेजी और कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मौके



पर टिवशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा और परिवार के अन्य सदस्य एम्स परिसर में मौजूद हैं। परिजन लगातार पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। भोपाल एम्स में शव सौंपने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टिवशा शर्मा के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। एम्स मॉंच्युरी के

बाहर शव वाहन आ गया है। टिवशा का अंतिम संस्कार शाम करीब पांच बजे भोपाल के भद्रभद्रा रमेशान घाट में किया जाएगा, जहां परिवार और करीबी लोग मौजूद रहेंगे। विधि-विधान के साथ टिवशा को अंतिम विदाई दी जाएगी।

एम्स की टीम सैपल लेकर हुई रवाना: दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय मेडिकल टीम ने टिवशा शर्मा के शव का करीब तीन घंटे में दोबारा पोस्टमॉर्टम किया। इस दौरान कई पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। पोस्टमॉर्टम पूरा होने के बाद मेडिकल टीम अपने साथ तीन बॉक्स में साक्ष्य और सैपल लेकर रवाना हुई है, जिन्हें आगे की जांच और एनालिसिस के लिए सुरक्षित रखा गया है। इधर, टिवशा शर्मा की अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अर्थी सजाने के लिए फूल लाए गए हैं। परिजन अंतिम संस्कार की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। टिवशा की अर्थी सजने से पहले उनकी मां रो रही थीं, जिन्हें परिजन संभालते नजर आए। परिवार और करीबी लोग उन्हें ढाढस बंधाने की कोशिश करते रहे।

भारतीय एथलेटिक्स के लिए गुरिंदर वीर सिंह का रिकॉर्ड ऐतिहासिक क्षण: उप राज्यपाल

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के उप राज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधु ने पंजाब के तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह को 10.09 सेकेंड की शानदार दौड़ लगाकर इतिहास रचने पर शुभकामनाएं देते हुए इसे भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उप राज्यपाल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि गुरिंदर वीर सिंह का 10.09 सेकेंड का शानदार स्प्लिट लगाकर देश का सबसे तेज धावक बनना अद्भुत उपलब्धि है जो देशभर के अनभिन्नत युवा एथलीटों को प्रेरित करेगी। उनका सफर इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एकप्रता, अनुशासन और अटूट समर्पण महानता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उप राज्यपाल ने कहा कि गुरिंदर वीर सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई



ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, पदक जीतते रहेंगे और कई और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों से भारत को गौरवान्वित करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि रांची में आयोजित फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दो दिनों में दो बार तोड़ दिया। शुक्रवार को 10.10 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद गुरिंदर वीर ने शनिवार को 10.09 सेकेंड की शानदार दौड़ लगाकर इतिहास रच दिया।

इंदौर में गहराया जल संकट, पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग, कांग्रेस का चक्काजाम प्रदर्शन

एजेंसी, इंदौर

मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पानी का संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। शहर के कई वाडों की कॉलोनियां और मोहल्ले इन दिनों भीषण जल किल्लत से जूझ रहे हैं। हालांकि इतने खराब हैं कि टैंकर पहुंचते ही पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। नगर निगम ट्रेक्टर-टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई कर रहा है, लेकिन बढ़ती मांग के सामने यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। इस बावत महापौर का कहना है कि वे इस गंभीर स्थिति की जानकारी है और कंट्रोल रूम से हर घर जल पहुंचाने को प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच जल संकट से परेशान लोगों ने रविवार को शहर के अलग-अलग हिस्सों में सड़क पर उतरकर



विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय निवासियों ने पालदा और सुखलिया में चक्काजाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पालदा चौराहे पर कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्ड-75

मजबूरी में लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है या दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान कुणाल सोलंकी ने कहा कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे और समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तब तक वे पानी नहीं पीएंगे। पार्षद ने जल संकट को लेकर विधायक मधु वर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कॉलोनियां में अब तक नर्मदा लाइन नहीं पहुंची है और नगर निगम से पर्याप्त टैंकर भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गोवा के सेक्सटॉर्शन रैकेट का मास्टरमाइंड सलमान खान दून से गिरफ्तार

एजेंसी, देहरादून

उत्तराखंड पुलिस और गोवा पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट के फरार सरगना सलमान खान को नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपित पिछले तीन वर्षों से फरार चल रहा था और गोवा में दर्ज करोड़ों रुपये की उगाही के मामले में वांछित था। एसटीएफ के अनुसार आरोपित सलमान खान, निवासी माजरा पटेलनगर, देहरादून, गोवा के मापुसा थाना क्षेत्र में दर्ज एक संगठित अपराध मामले में शामिल था। आरोप है कि उसने अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर एक सेक्सटॉर्शन गिरोह बनाया था, जो अमीर कारोबारियों को निशाना बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। जानकों सामने आया कि गिरोह महिलाओं के माध्यम से कारोबारी लोगों को जाल में फंसाता था। इसके बाद फर्नर नारकोटिक्स ब्यूरो अधिकारी बतारकर मौके पर पहुंचे और कारोबारी को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए भारी रकम वसूल की।



महिला के जरिए फंसाते थे कारोबारी, अरलील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल

मुताबिक गिरोह ने गोवा के मापुसा क्षेत्र में एक विला किराये पर लेकर वहां गुप्त कैमरे लगाए थे। योजना के तहत मुंबई के एक कारोबारी को वहां बुलाया गया, जहां महिला सहयोगी के साथ उसके वीडियो रिकॉर्ड किए गए। बाद में गिरोह के सदस्य खुद को दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो का अधिकारी बताकर मौके पर पहुंचे और कारोबारी को बंधक बनाकर मारपीट करते हुए भारी रकम वसूल की।

इबोला पर केंद्र सरकार का देशवासियों को परामर्श कांवो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने से बचें

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने इबोला प्रभावित देशों में बदलती स्थिति को देखते हुए और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की सिफारिशों के अनुरूप सभी भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर-पतलू यात्रा से बचने की सलाह दी है। कांगो, युगांडा और उसकी सीमा से लगे दक्षिण सूडान और अन्य देशों में बीमारी फैलने सबसे अधिक खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार भारतीय नागरिक जो वर्तमान में इन देशों में रह रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें और अतिरिक्त सावधानी बरतें। डब्ल्यूएचओ की



आपातकालीन समिति ने 22 मई को आगमन के प्रवेश बिंदुओं पर बीमारी की निगरानी को मजबूत करने के लिए कुछ अस्थायी सिफारिशें जारी कीं। इन सिफारिशों में 'बुंडिबुग्यो वायरस पाए जाने वाले क्षेत्रों की यात्रा न करने' की भी सलाह दी गई है। भारत में बुंडिबुग्यो वायरस स्ट्रेन के कारण होने वाली इबोला बीमारी का अबतक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इबोला रोग एक

वायरल हेमोरेजिक बुखार है, जो इबोला वायरस के 'बुंडीबुग्यो' स्ट्रेन के संक्रमण के कारण होता है। यह एक गंभीर बीमारी है, जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक है। वर्तमान में बुंडीबुग्यो स्ट्रेन का कारण होने वाले इबोला रोग की रोकथाम या उपचार के लिए किसी भी टीके या विशिष्ट उपचार को मंजूरी नहीं दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 के तहत 17 मई को इस स्थिति को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया था। अफ्रीकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा को प्रभावित करने वाले बुंडिबुग्यो स्ट्रेन इबोला वायरस रोग के मौजूदा प्रकोप को आधिकारिक तौर पर 'महाद्वीपीय सुरक्षा का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित किया है।

कानूनी मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) संशोधन नियम, 2026 लागू- सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन पंपों पर नहीं होगी माप-तौल में हेराफेरी :कानूनी मापन व्यवस्था में बड़े सुधार की ओर भारत का निर्णायक कदम -समग्र व्यापक विश्लेषण



एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

गोंदिया - वैश्विक स्तर पर भारत में ईंधन वितरण प्रणाली लंबे समय से उपभोक्ता विश्वास, पारदर्शिता और माप- तौल की सटीकता से जुड़ा एक संवेदनशील विषय रही है। पेट्रोल पंपों पर कम ईंधन देने की शिकायतें हों या उभरते स्क्वर्ड ईंधन क्षेत्रों,सीएनजी, एलपीजी,एलएनजी और हाइड्रोजन, में मानकीकरण की चुनौती, सरकार के सामने एक ऐसी विश्वसनीय व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता थी जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ आधुनिक ऊर्जा अर्थव्यवस्था की जरूरतों को भी पूरा कर सके। इसी दिशा में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग,उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा कानूनी मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) संशोधन नियम, 2026 लागू किए गए हैं, जो 8 मई 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गए, जिसके लिए विधि मापन संबंधी सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र संशोधन नियम, 2026 के मसौदे पर हितधारकों से टिप्पणियाँ 1 से 31 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की गई थीं।इस संशोधन का मूल उद्देश्य भारत की कानूनी मापन प्रणाली को अधिक पारदर्शी,वैज्ञानिक, तकनीक-सक्षम और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। नए नियमों के

» कानूनी मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा, उपभोक्ता संरक्षण और प्रशासनिक सुधार यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव
 » पेट्रोल से लेकर हाइड्रोजन तक सभी प्रमुख ईंधन वितरण प्रणालियों को वैज्ञानिक सत्यापन ढांचे में शामिल करना भविष्य की अर्थव्यवस्था पारदर्शिता, तकनीकी सटीकता व उपभोक्ता विश्वास पर आधारित होने का स्पष्ट संकेत -एडवोकेट किशन षणमुख दास भावनी गोंदिया महाराष्ट्र

अंतर्गत पहली बार पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर, सीएनजी डिस्पेंसर, एलपीजी डिस्पेंसर, एलएनजी डिस्पेंसर और हाइड्रोजन डिस्पेंसर को सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) ढांचे में शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब इन ईंधन वितरण प्रणालियों का सत्यापन और पुनःसत्यापन अधिक व्यवस्थित तेज और व्यापक स्तर पर हो सकेगा। यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को सही मात्रा में ईंधन सुनिश्चित करेगा बल्कि भारत में स्क्वर्ड ऊर्जा संक्रमण, हरित ईंधन अवसंरचना और डिजिटल प्रशासन को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि भारत में लीगल मेट्रोलाजी अर्थात कानूनी मापन व्यवस्था का महत्व केवल व्यापारिक लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ता संरक्षण,निष्पक्ष बाजार व्यवस्था और आर्थिक विश्वसनीयता की आधारशिला भी है। जब कोई



उपभोक्ता पेट्रोल,सीएनजी या एलपीजी खरीदता है, तो वह वस्तुतः मात्रा और मूल्य के बीच एक कानूनी अनुबंध कर रहा होता है।यदि माप में गड़बड़ी होती है तो यह सीधा आर्थिक शोषण माना जाता है। इसी कारण दुनियाँ के विकसित देशों में ईंधन वितरण प्रणालियों के लिए अत्यंत कठोर सत्यापन मानक लागू किए जाते हैं। भारत में भी लंबे समय से विधिक मापन अधिनियम और संबंधित नियम लागू हैं, किंतु बदलती तकनीकों और ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार के कारण नई चुनौतियाँ सामने आ रही थीं।विशेष रूप से सीएनजी और हाइड्रोजन जैसे गैसीय ईंधनों के वितरण में उच्च तकनीकी सटीकता की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकार द्वारा जीएटीसी ढांचे का विस्तार करना एक समर्थोचित और दूरदर्शी निर्णय माना जा रहा है। साथियों, यह संशोधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे भारत में एक समान रूप से लागू होने वाला केंद्रीय नियम है। यानी 8 मई 2026 से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह व्यवस्था प्रभावी हो चुकी है। हालाँकि, केंद्र सरकार ने राज्यों को भी पर्याप्तलचीलाना दिया है। संशोधन के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और औद्योगिक जरूरतों के आधार पर अतिरिक्त श्रेणियों के वजन एवं माप उपकरणों को सत्यापन के लिए अधिसूचित कर सकें। इससे संघीय ढांचे और स्थानीय प्रशासनिक

श्रेणियों में पेट्रोल/डीजलडिस्पेंसर सीएनजी डिस्पेंसर, एलपीजी डिस्पेंसर, एलएनजी डिस्पेंसर और हाइड्रोजन डिस्पेंसर शामिल हैं। यह सूची इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल पारंपरिक ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहना चाहता,बल्कि वह भविष्य की हरित ऊर्जा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियामक ढांचा विकसित कर रहा है। विशेष रूप से हाइड्रोजन डिस्पेंसरों को शामिल करना अत्यंत दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है और भारत भी राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से इस क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रहा है। ऐसे में यदि वितरण प्रणाली का सत्यापन वैज्ञानिक और पारदर्शी नहीं होगा तो भविष्य में बड़े स्तर पर उपभोक्ता विवाद और तकनीकी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती थीं। सरकार ने समय रहते इस दिशा में नियामक ढांचे को मजबूत कर दिया है।सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन जैसे ईंधनों का वितरण सामान्य तरल ईंधनों की तुलना में कहीं अधिक जटिल होता है। इनमें दबाव, तापमान और गैस घनत्व जैसे कई वैज्ञानिक कारक शामिल होते हैं। यदि माप उपकरणों का समय पर अंशान्कन और सत्यापन न किया जाए तो वितरण में बड़ी त्रुटियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसका प्रभाव केवल उपभोक्ता के आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा जोखिम भी बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और इसकी आपूर्ति में तकनीकी मामलों की अनदेखी गंभीर दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है। इसलिए इन नई श्रेणियों को कानूनी मापन ढांचे में शामिल करना ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। साथियों, सरकार द्वारा सत्यापन शुल्क भी स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है। संशोधित नियमों के अनुसार पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसरों के

सत्यापन शुल्क को 5,000 रुपये प्रति नोजल तथा सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों के लिए 10,000 रुपये प्रति नोजल निर्धारित किया गया है। पहली नजर में यह शुल्क कुछ संचालकों को अधिक लग सकता है, लेकिन यदि इसे उपभोक्ता संरक्षण और तकनीकी विश्वसनीयता के संदर्भ में देखा जाए तो यह निवेश दीर्घकालिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। सही सत्यापन व्यवस्था उपभोक्ता विवादों को कम करेगी,ईंधन चोरी और माप-तौल में हेराफेरी पर अंकुश लगाएगी तथा व्यवसायों की विश्वसनीयता बढ़ाएगी।इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना भी है। नियमों में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ताकि अनुमोदन और संबंधित प्रशासनिक मामलों का त्वरित निरासन हो सके। भारत जैसे विशाल देश में अक्सर तकनीकी स्वीकृतियों और प्रमाणन प्रक्रियाओं में देरी एक बड़ी समस्या रही है। यदि सत्यापन और अनुमोदन समय पर नहीं हो पाते, तो उद्योगों की लागत बढ़ती है और उपभोक्ताओं को भी असुविधा होती है। इसलिए यह संशोधन केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार भी है। साथियों, यह पहल ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब सत्यापन सेवाएँ अधिक उपलब्ध और तेज होंगी, तो उद्योगों को संभालने में आसानी होगी। इससे ईंधन वितरण नेटवर्क के विस्तार में तेजी आएगी। विशेष रूप से सीएनजी और एलएनजी आधारित परिवहन अवसंरचना को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। भारत पहले ही प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है और अनेक शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। ऐसे में सत्यापन क्षमता का विस्तार ऊर्जा क्षेत्र के विकास को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन

देगा।उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखें तो यह संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में लंबे समय से ईंधन पंपों पर कम मात्रा में ईंधन देने की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई बार इलेक्ट्रॉनिक छेड़छाड़, पालत अंशान्कन या तकनीकी गड़बड़ियों के कारण उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ता था। अब अधिक संख्या में सत्यापन केंद्र उपलब्ध होने से नियमित जांच और पुनः सत्यापन संभव होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त राज्य के विधिक माप विभाग अब सत्यापन संबंधी कार्यभार से कुछ हद तक मुक्त होकर निरीक्षण, प्रवर्तन और उपभोक्ता शिकायत निवारण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। विशेष रूप से केंद्रित कर सकेंगे। साथियों, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी यह कदम महत्वपूर्ण है। दुनिया के अधिकांश विकसित देश अपने कानूनी मापन ढांचे को अंतरराष्ट्रीय विधिक मापन संगठन यानी ओआईएमएल की सिफारिशों के अनुरूपविकसित कर रहे हैं। भारत का यह संशोधन भी वैश्विक सर्वोच्च प्रथाओं के अनुरूप माना जा रहा है। इससे भारतीय मापन प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ेगी और वैश्विक व्यापार में भी लाभ मिलेगा। विशेष रूप से जब भारत स्क्वर्ड ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और वैकल्पिक ईंधनों के क्षेत्र में वैश्विक निवेश आकर्षित करना चाहता है, तब एक मजबूत और वैज्ञानिक मापन प्रणाली निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सटीकता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथियों कानूनी मापन प्रणाली का महत्व केवल व्यापार पारदर्शिता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक आर्थिक शासन का भी हिस्सा है। यदि किसी देश में माप-तौल की प्रणाली विश्वसनीय नहीं होती, तो बाजार में उपभोक्ता विश्वास कमजोर पड़ता है और आर्थिक गतिविधियों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए विकसित

अर्थव्यवस्थाएँ इस क्षेत्र में अत्यधिक निवेश करती हैं। भारत द्वारा जीएटीसी ढांचे का विस्तार इसी दिशा में एक संरचनात्मक सुधार है जो भविष्य में डिजिटल मापन तकनीकों, स्मार्ट डिस्पेंसर और एआई आधारित निगरानी प्रणालियों के लिए भी आधार तैयार करेगा।यह संशोधन आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। जब देश अपनी ऊर्जा अवसंरचना , सत्यापन क्षमता और तकनीकी मानकीकरण को मजबूत करता है, तो वह आयातित प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है। साथ ही घरेलू उद्योगों और तकनीकी प्रयोगशालाओं को नए अवसर भी प्राप्त होते हैं। जीएटीसी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कहा जा सकता है कि कानूनी मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) संशोधन नियम, 2026 केवल एक तकनीकी संशोधन नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा, उपभोक्ता संरक्षण और प्रशासनिक सुधार यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। पेट्रोल से लेकर हाइड्रोजन तक सभी प्रमुख ईंधन वितरण प्रणालियों को वैज्ञानिक सत्यापन ढांचे में शामिल करके सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था पारदर्शिता, तकनीकी सटीकता और उपभोक्ता विश्वास पर आधारित होगी। आने वाले वर्षों में जब भारत स्क्वर्ड ऊर्जा आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका मजबूत करेगा, तब वह विश्वनीयता का महत्वपूर्ण आधार बनेगा।

-संकलनकर्ता लेखक - क्रर विशेषज्ञ रत्नभक्त साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

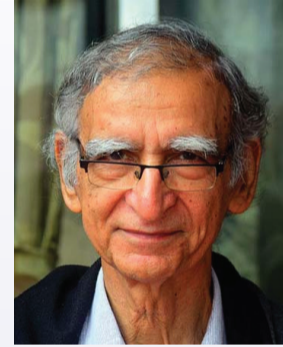
मीडिया : हमको आईना दिखाना है दिखा देते हैं



लेखक - तनवीर जाफ़री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात,नोदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली देशों का दौरा किया। इस दौरान नॉर्वे की एक घटना ने एक बार फिर मीडिया उसके कर्तव्य व दायित्व को लेकर बहस छेड़ दी। दरअसल ओस्लो में जब मोदी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ जैसे ही मंच से जाने लगे उसी समय एक युवा महिला पत्रकार हेला लिंग ने मोदी को संबोधित करते हुये कुछ सवाल पूछे। हेला लिंग ने पूछा प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते? मोदी पत्रकार के सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए। इस घटना के फ़ौरन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा उसी जगह एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस बुलाई गई जिसमें पत्रकार हेला लिंग को भी बुलाया गया। वहाँ भी हेला लिंग ने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर कई तीखे सवाल पूछे, जिस पर भारतीय अधिकारियों ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और विकास का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। परन्तु नॉर्वे की इस घटना पर भारतीय गोदी मीडिया ने युवा साहसी महिला पत्रकार हेला लिंग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें मीडिया के कर्तव्य व दायित्व बोध का पाठ पढ़ने लगा। गोदी मीडिया ने महिला पत्रकार के इस तरीके को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की रणनीति करार दिया। वहाँ भारत के ही स्वतंत्र, डिजिटल,वैकल्पिक,निष्पक्ष व सोशल मीडिया ने पत्रकार हेला की जमकर तारीफ़ की। इस वर्ग ने हेला लिंग के साहस की सराहना की और इसे सच्ची पत्रकारिता का उदाहरण बताया तथा इस पूरी घटना को वैश्विक स्तर पर प्रेस की आजादी और लोकतंत्र में जवाबदेही से जोड़कर देखा। कुछ स्वतंत्र विचारकों और कई सोशल मीडिया

पोर्टल्स ने तो इस अवसर का प्रयोग उन गोदी पत्रकारों पर तंज कसने के लिए किया जो सत्ता से सवाल पूछने के बजाये सत्ता की खुशामद में लगे रहते हैं। यही वजह है कि जो सवाल भारत के शीर्ष मुख्यधारा के पत्रकारों को पूछने चाहिए थे वही सवाल एक विदेशी पत्रकार को पूछने पड़ रहे हैं। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अब तक एक भी नियमित संवाददाता सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। अपने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं बताया था कि वे पुरानी परिपाटी जहाँ नेता मीडिया के माध्यम से अपनी बात प्रसारित करते थे, के बजाय सीधे जनता के बीच जाकर काम करने और नई कार्य संस्कृति स्थापित करने पर विश्वास रखते हैं। मन की बात,सार्वजनिक रैलियाँ,युवावी सभाएँ, सम्पादकीय फ़ूट के अपने आलेख,किसी कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जन सभा आदि के माध्यम से जनता से इकतरफ़ा संवाद करना प्रधानमंत्री का पसंदीदा तरीका है। जबकि भारत के लाभग सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यह नियमित परंपरा रही थी कि वे विदेश दौरों से लौटने,विमान में या देश में समय-समय पर खुली प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित किया करते थे। सच तो यह है कि मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मीडिया से जुड़े उनके कुछ ऐसे कटु अनुभव रहे हैं जिसके चलते वे अब पुनः साहसी पत्रकारों से रूबरू होकर पुनः अपनी वैसी फ़जीहत नहीं कराना चाहते। याद कीजिये अक्टूबर 2007 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे,उस समय बरिष्ठ पत्रकार करण थापर ने सी एन एन-आई बी एन के प्रसिद्ध शो डेविल्स एडवोकेट के लिए अहमदाबाद में मोदी का इंटरव्यू लिया था। करण थापर ने मोदी से अपने पहले सवाल में ही 2002 के गुजरात दंगों को लेकर पूछा कि ढांचे के पांच साल बाद भी उनकी छवि एक क्रूर शासक की बनी हुई है, इसे सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? जब मोदी ने कहा कि जनता उन्हें अच्छे से जानती है, तो थापर ने आला सवाल किया कि आप यह क्यों नहीं कह देते कि आपको दंगों में मारे गए लोगों का दुख या पछतावा है? क्या सरकार को मुसलमानों की सुरक्षा के लिए और कदम नहीं उठाने चाहिए थे?



लेखक - राम पुन्यवानी

स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति पुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित थी और वह शीत युद्ध के दोनों प्रमुख पात्रों - अमेरिका और सोवियत संघ - में से किसी के सामने नहीं झुकता था। पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका के इशारों पर नाचता रहा और वहां लोकतंत्र का गला घोटकर मुस्लिम साम्राज्यिक राजनीति का बोलबाला स्थापित होने में अमेरिकी राजदूत, मुल्लाओं और सेना की भूमिका सबसे सामने साफ़ थी। आज भी इस्लाम के नाम पर वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है और सेना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वहां एक के बाद एक सेना के जनरल सत्ता पर काबिज रहे या राजनैतिक मामलों में उनका

आरएसएस-भाजपा और अमेरिका की दासता की ओर बढ़ता भारत

जबरदस्त हस्तक्षेप रहा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ़ील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर को भोज का आमंत्रण दिए जाने से पाकिस्तान के हलाल क्या है, यह अच्छे से समझा जा सकता है। वैसे पाकिस्तान की विदेश नीति के अन्य पक्ष भी हैं, लेकिन उसका अमेरिका की ओर झुकवा एकदम स्पष्ट रहा है। मजाक में यह कहा जाता था कि पाकिस्तान पर तीन 'ए' का राज है - अल्लाह, अमेरिकी राजदूत और आर्मी। यह कथन संभवतः अतिशयोक्तिपूर्ण हो लेकिन सत्य है कि जब समाज में धर्म के नाम पर की जाने वाली राजनीति का बोलबाला हो जाता है, तब वैसे ही हालात बन जाते हैं जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में हैं। भारत किसी भी महाशक्ति के सामने न झुकने की राह पर चला और विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग से बहुआयामी विकास करते हुए उसने तकनीकी, औद्योगिक और शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हासिल की। इसका एक उदाहरण है वे पांच आईआरटी, जिन्हें से प्रत्येक अलग-अलग बड़े देशों की मदद से बनाए गए। भारत महाशक्तियों दबाव के सामने नहीं झुका, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश की स्थापना के पहले की घटनाएँ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हमारे परंपरागत रिश्तों को कुर्बान कर दिया गया है। आपोरेशन सिंद्

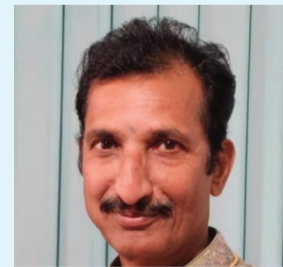
न करे। उस समय पाकिस्तान की सेना वहां कहर द्वा रही थी, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे। इंदिरा गांधी ने निर्भीकता का परिचय देते हुए न केवल निक्सन की सहाय मानने से इंकार कर दिया बल्कि सोवियत संघ के साथ 'मैत्री संधि' कर ली और बंगाल में अमेरिकी नौसेना के सातवें बेड़े की मौजूदगी के बावजूद भारतीय सेना ने वहां हस्तक्षेप किया और मुक्ति वाहिनी की पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराने में मदद की, जो पूर्वी पाकिस्तान में तरह-तरह की ज्यादतियों कर रहा था। यहां तक कि पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा उर्दू को पूर्वी पाकिस्तान पर लादने का प्रयास किया जा रहा था। बांग्लाभाषी पूर्वी पाकिस्तान ने बग़ावत कर दी। भारत ने अमेरिकी धमकियों की परवाह न करते हुए पूर्वी पाकिस्तान की जनता को मुक्ति दिलवाई। लेकिन 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में धीरे-धीरे बदलाव होता गया और सत्ता पर अमेरिका का प्रभुत्व कायम होता गया। भारत, इजराइल के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर रहा है। सत्ता पर काबिज दल की नीतियों के अनुरूप ईरान और फिलीस्तीन से हमारे परंपरागत रिश्तों को कुर्बान कर दिया गया है। आपोरेशन सिंद्

में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच टकराव हुआ। जहां भारत ने दावा किया कि युद्धविराम पाकिस्तान के अनुरूप और दोनों देशों के बीच हुई वार्ताओं की वजह से हुआ, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार यह शेखी बघारी कि उनके प्रशासन से आर्थिक मामलों में नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर दोनों देशों के बीच युद्धविराम करवाया। अब तक भारत में पाकिस्तान को देश का दुश्मन नंबर 1 बताया जाता रहा है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच इंडो-पाक फोरम व अमन की आशा जैसी महत्वपूर्ण पहलों के जरिए संपर्क-संबंध स्थापित करने के प्रयास होते रहे हैं। अमन की आश अभियान की शुरूआत भारत के टाइम्स ऑफ़ इंडिया एवं पाकिस्तान के अग्रणी दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक शानदार कदम था। होसबोले का दावा है कि संघ की नीति हमेशा से यही रही है, और नागरिक इलाकों में भारतीय सेना की भारी मौजूदगी ने उनका जीवन हाराम कर दिया। अब ऐसा लगता है कि आरएसएस-भाजपा का पाकिस्तान के प्रति रूख बदल रहा

है। आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े नेता सरकारीवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने हाल में कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। संघ परिवार लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है और नेहरू को कश्मीर की स्थिति के लिए दोषी ठहराता रहा है। इसी बीच कश्मीर में अफ़रातफ़री जारी रही। अल्लबिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच विवाद को सुलझाने के प्रयास में लाहौर तक बस यात्रा की। इसके बाद पाकिस्तान के तानाशाह परवेज मुशरफ़ भारत पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी गतिरोध बना रहा। इस सबके बीच होसबोले का वक्तव्य हवा के एक ताजे झोंके की तरह है। आरएसएस के मुखिया होने भागवत पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को अखंड भारत की संकल्पना से जोड़ते रहे हैं। भाजपा सरकार ने सार्क को बढ़ावा देने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक शानदार कदम था। होसबोले का दावा है कि संघ की नीति हमेशा से यही रही है, हालांकि सच यह है कि बातचीत के द्वार खुले रखने की बात एकदम अपनी है। होसबोले ने यह वक्तव्य अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के बाद जारी किया है मगर कई लोगों को संदेह है

कि उन्होंने अमेरिका के दबाव में ऐसा कहा है। इस दावे की सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत अमेरिका को अपना आका मान चुका है। अमेरिका ने जब भारत पर आयात शुल्क 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया और उसे फिर 18 प्रतिशत तक घटा दिया तब भारत ने इसका कोई विरोध नहीं किया। भारत ने बिना ना-नुकुर के अमेरिका के इस निर्देश का भी पालन किया कि वह रूस से कच्चा तेल न खरीदे। इसकी दुबारा पुष्टि राम माधव के उस वक्तव्य से हुई जिससे वे बाद में पीछे हट गए। वे आरएसएस-भाजपा के प्रमुख नेता हैं। वाशिगटन में हइसन इंटीटीयूट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत टेरिफ बढ़ाने और रूस से तेल न खरीदने जैसे अमेरिका के फैसलों और मांगों के सामने झुका। इसके बाद उन्होंने कहा कि "भारत ने अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए आखिर क्या नहीं किया"। जब उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपना यह वक्तव्य वापिस ले लिया मगर पोल तो खुल चुकी थी। आरएसएस हमेशा से अमेरिका का पिछलग्गू रहा है। यहां तक कि उसने अमेरिका के वियतनाम पर हमले का भी समर्थन किया था।

वन विभाग की उपेक्षा एवं वनों बढ़ती कटाई; इससे हिंसक जानवरों के कारण जनहानि हो रही है



रमेश कुलकार

देश में औद्योगीकरण, शहरीकरण, सीमेंट सड़कें, अप्रतिबंधित निर्माण और कुछ जगहों पर धर्म के नाम पर वृक्ष कटाई बढ़े पैमानेपर होरही है और सरकार इस मामले को खुली आंखों से देख रही है, लेकिन वह कान और मुंह पर हाथ रखकर तमाशबान की भूमिका में है। इसका नतीजा यह है कि इंसानों और पालतू जानवरों पर हिंसक जानवरों (बाघ, तेंदुआ, भालू) की आक्रामकता बढ़ रही है। देखने में आ रहा है कि पौधाशोषण

बारे में सोचें तो भारत के 50 शहरों में सूरज की तपिश का होना देश के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि देश में तापमान दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आले 7 दिनों तक तापमान बढ़ने की बात कही जा रही है. इसके चलते इस राज्य के कई शहर 'रेड अलर्ट' पर हैं। आज महाराष्ट्र समेत देश के कई शहरों का तापमान अपनी पूरी सीमा रेखा पर कर चुका है और देखा जा रहा है कि यह 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. आज विदर्भ गर्मीसे बेहल है,येसा देखा गया है की, वर्धा-७9.१, ब्रह्मपुरी -७9.२, नागपुर -४६.६, अमरावती -४६.४, चंद्रपुर -46.2 और अन्य शहर उच्चतम तापमान पर पहुंच गए हैं और 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुके हैं। इससे जंगली जानवरों को पार पाने के लिए जंगल में भटकना पड़ रहा है। क्योंकि जंगल में जलस्रोत भी सूख गये हैं. बदलती जलवायु,

बढ़ते तापमान और वनों की कटाई के कारण जंगल में जानवरों के लिए जल संसाधन खत्म हो गए हैं और बाघ और तेंदुए जैसे शिकारी जानवर गाँव या गाँव या शहर के आसपास के इलाकों की ओर भागते देखे जाते हैं। तो वहीं आज चंद्रपुर जिले के गुंजेवाही इलाके में बाघ के हमले में चार महिलाओं की मौत हो गई है. पिछले पांच वर्षों में, 2021-25 के दौरान चंद्रपुर जिले में वन्यजीव हमलों में 200 लोगों की मौत हो गई है और चालू वर्ष के पांच महीनों में यह संख्या 19 तक पहुंच गई है। इस तरह अब तक 219 लोगों की मौत हो चुकी है. लेकिन यह दुखद है कि सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सरकार को ऐसी गंभीर घटनाओं के लिए स्याई समझाना योजना लागू करनी होगी तभी हिंसक जानवरों पर कानूनी पाया जा सकेगा। वन विभाग और सरकार की ओर से वास्तविक उपाय नहीं किये जाने के कारण

यह बेहद चिंताजनक और गंभीर मुद्दा है. जैसा कि संबंधित है, पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बढ़ते तापमान और घटती वन संपदा के कारण यह स्पष्ट है कि हिंसक जानवर इंसानों पर हमला करने का रुख अस्विक्यार कर चुके हैं। चंद्रपुर जिले में तेंदू पत्ता संग्रहण कई वर्षों से चल रहा है। इस संग्रह से हर साल 35 हजार परिवारों को रोजगार मिलता है। चूंकि गर्मियों में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए कई परिवार तेंदू पत्ते इकट्ठा करने और अपनी आजीवनिक कमाने के लिए जंगल में जाते हैं। इस बात से वन विभाग और सरकार भलीभांति परिचित है, इसके बावजूद यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इच्छ है कि सरकार जंगली जानवरों से बचाने में असमर्थ है. महाराष्ट्र में जंगली जानवरों के हमलों से जिनकी जनहानि अत्यंत चिंताजनक है। 2021 में 93, 2021 में 118, 2022 में 134, 2023 में 147,

2024 में 167 और 2025 से मै तक हिंसक जानवरों के कारण 72 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संपूर्ण मानव हानि वनों की कटाई के कारण होने वाली एक बड़ी समस्या है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है". महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने नुकसान रोकने के लिए बकरियों को जंगल में छोड़ने की बात कही थी. हालांकि, यह बहुत गंभीर मामला है कि हम जंगली जानवरों के कारण बड़ी मात्रा में मानवीय क्षति देखते हैं। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अत्यधिक गर्मी के कारण बाघ और अन्य जंगली जानवर आक्रामक हो रहे हैं। हिंसक जानवरों से होने वाली जनहानि की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस पर तत्काल कदम उठाने चाहिए। जय हिन्द.

लेखक-रमेश कुलकार लांजेवार (स्वतंत्र पत्रकार) मो.नं.9921690779, नागपुर

100 मीटर स्प्रिंट में 10.09 सेकंड का समय निकाल तोड़ा रिकॉर्ड

रांची, एजेंसी। पंजाब के उभरते हुए धावक गुरिंदरवीर सिंह ने भारतीय एथलेटिक्स में नया इतिहास रच दिया है। रांची में आयोजित 2026 एथलेटिक्स फेडरेशन कप में गुरिंदरवीर ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते हुए 10.09 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही वह 100 मीटर दौड़ में 10.10 सेकंड से कम समय निकालने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद पंजाब से लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी और इसे पंजाब के लिए गर्व का क्षण बताया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी बधाई

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कहा, 'हमारे होनहार खिलाड़ी गुरिंदरवीर सिंह को रांची में फेडरेशन कप की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। गुरिंदरवीर इतने कम समय में रस पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। पंजाब के बेटे ने लगातार दो दिनों में दूसरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर राज्य का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है।'

परिवार को बेटे पर गर्व

गुरिंदरवीर की मां रूपिंदर कौर ने बेटे की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा, 'हमें बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बेटे ने इतिहास रच दिया। रिश्तेदार लगातार फोन करके बधाई दे रहे हैं। बचपन से ही वह बहुत खुशामिजाज था। उसके कोचों ने भी काफी मेहनत की। उसके पिता का सपना था कि वह एथलीट बने। मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि माता-पिता की बात सुनें, पढ़ाई और खेल दोनों पर ध्यान दें और नशे से दूर रहें।' मैं खुद वॉलीबॉल खेलता था और चाहता था कि वह खिलाड़ी बने। खेल ही ऐसा मंच है जहाँ आप अपना नाम बनाते हैं और माता-पिता व कोच को गर्व महसूस कराते हैं।'

कोच ने बताया मेहनत का सफर

गुरिंदरवीर के कोच सरबजीत सिंह ने कहा कि खिलाड़ी ने पिछले 10 वर्षों तक उनके साथ कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुरिंदरवीर ने मेरे साथ 10 साल तक ट्रेनिंग की। जैसे ही उसने सेमीफाइनल में अनीमेष का रिकॉर्ड तोड़ा, उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने ऐतिहासिक रस दोड़कर पंजाब का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया।'

कॉमनवेल्थ गेम्स पर नजर

गुरिंदरवीर ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान ट्रेनिंग पर रहेगा और वह भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने साथी धावक अनीमेष कुजूर और मणिकांत का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत प्रतिस्पर्धा खिलाड़ियों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।

मानसिक मजबूती बनी सफलता की कुंजी

गुरिंदरवीर सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, कोच और सपोर्ट स्टाफ को दिया। उन्होंने कहा, 'यह बहुत शानदार एहसास है। मैं आगे भी कड़ी ट्रेनिंग करके अच्छे नतीजे लाना चाहता हूँ। आखिरी समय में खेल शारीरिक से ज्यादा मानसिक मजबूती का होता है। मैं खुद को मानसिक रूप से मजबूत रख पाया और इसी वजह से अच्छा प्रदर्शन कर सका।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अपने परिवार, कोच, डाइटिशियन और रिलायंस फाउंडेशन को श्रेय देना चाहता हूँ। सभी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे बेहतरीन सुविधाएं दीं।'

बधाइयों का लगा तांता



राष्ट्रमंडल खेलों से पहले गुलवीर सिंह सुर्खियों में! तोड़ा 5000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड

लॉस एंजेलिस। भारत के स्टा रलबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया है। लॉस एंजेलिस में आयोजित एलए ट्रेक फेस्टिवल में गुलवीर ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुलवीर ने 13 मिनट 03.93 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में इथीयोनिया के हबतोम सैमुअल ने 12:57.22 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय धावक ने अपने पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13:11.82 को पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने सितंबर 2024 में जापान में बनाया था।



बनाया। उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा और भारतीय लंबी दूरी की दौड़ को नई पहचान दी है। पोस्ट में आगे कहा गया, 'गुलवीर अनुशासन, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाईयों तक ले जा रहे हैं।'

भारतीय एथलेटिक्स के नए सितारे

गुलवीर सिंह फिलहाल अमेरिका के कोलोराडो स्पिंग्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वह 3000 मीटर से लेकर 25 किलोमीटर रोड रस तक कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उनके नाम 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10000 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं। इसके अलावा वह 5000 मीटर और 10000 मीटर में मौजूदा एशियाई चैंपियन भी हैं। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 5000 और 10000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था।

इस साल लगातार शानदार प्रदर्शन

यह 2026 में गुलवीर का चौथा बड़ा मुकाबला था। उन्होंने साल की शुरुआत जनवरी में वर्ल्ड क्रॉस कट्टी चैंपियनशिप से की, जहां वह सीनियर पुरुष वर्ग में 40वें स्थान पर रहे। फरवरी में अमेरिका के विंस्टन-सेलम में आयोजित साउंड रनिंग इनवाइट में उन्होंने 5000 मीटर शॉर्ट ट्रैक में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद मार्च में न्यूयॉर्क हाफ मैराथन में उन्होंने 59 मिनट 42 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और एक घंटे से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय बने। इससे पहले भारत का रिकॉर्ड अविनाश साबले के नाम था, जिन्होंने 2020 दिल्ली हाफ मैराथन में 1:00:30 का समय निकाला था।

प्लेऑफ से पहले आरसीबी को लगा तगड़ा झटका इंग्लैंड का ये विस्फोटक बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट से बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबलों से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बेथेल अब इंग्लैंड लौटेंगे, जहां उनकी चोट का आगे इलाज और मेडिकल जांच की जाएगी। यह खबर केच पकड़ने की कोशिश में डेवद लगाते हुए उनकी बाएं हाथ की रिंग फिंगर चोटिल हो गई थी। इसी वजह से वह सनराइजर्स

हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी के आखिरी लीग मैच में भी नहीं खेले थे। आरसीबी ने शनिवार को कहा, 'जैकब बेथेल को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान बाएं हाथ की रिंग फिंगर में चोट लगी। मेडिकल जांच के बाद वह आगे के मूल्यंकन के लिए इंग्लैंड लौटेंगे।' इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भी खिलाड़ी की वापसी की पुष्टि की है। बोर्ड के अनुसार, बेथेल की मेडिकल टीम लगातार निगरानी करेगी ताकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए उनकी उपलब्धता तय की जा सके। आरसीबी ने इस सीजन शानदार प्रदर्शन करते हुए अंक तालिका में टॉप स्थान हासिल किया था। हालांकि, प्लेऑफ से ठीक पहले बेथेल का बाहर होना टीम के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। वहीं,

टीम के लिए राहत की खबर यह है कि स्टा ओपनर फिल सांल्ट की वापसी हो चुकी है। उम्मीद है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर-1 में वह सीधे प्लेइंग इलेवन में नजर आएंगे। **वेकेंडेश अय्यर ने निभाई थी ओपनिंग की जिम्मेदारी-** सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मुकाबले में ऑलराउंडर वेकेंडेश अय्यर ने ओपनिंग करते हुए 19 रनों में तेज 44 रन बनाए थे। लेकिन फिल सांल्ट की वापसी के बाद उनके मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने की संभावना है। आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का क्वालिफायर-1 मुकाबला जल्द खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम सीधे फाइनल में जगह बनाएगी।

हैरी केन की हैट्रिक से बायर्न म्यूनख ने जीता जर्मन कप, बुंदेसलीगा के बाद जीता दूसरा खिताब



म्यूनख, एजेंसी। हैरी केन की शानदार हैट्रिक की बदौलत बायर्न म्यूनख ने डीएफबी-पोकाल (जर्मन कप) फाइनल में स्टटगार्ट को 3-0 से हराकर चतुर्थ डबल अपने नाम कर लिया। बायर्न ने इस जीत के साथ अपना 21वां जर्मन कप खिताब जीता और 2020 के बाद पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इससे पहले टीम इस सीजन में बुंदेसलीगा का खिताब भी जीत चुकी है। बायर्न के इतिहास में यह 14वां मौका है जब क्लब ने एक ही सीजन में लीग और कप दोनों खिताब जीते हैं। वहीं स्टटगार्ट का सीजन बिना किसी ट्रॉफी के समाप्त हुआ।

पहले हाफ में स्टटगार्ट ने दी कड़ी टक्कर

मैच की शुरुआत में स्टटगार्ट ने आक्रामक खेल दिखाया और बायर्न को दबाव में रखा। शुरुआती मिनटों में डेगो जंडाव और एंजेलो स्टिलर ने गोल करने के मौके बनाए, लेकिन बायर्न के गोलकीपर जोनास उरविग ने शानदार बचाव किया। मैनुअल नोयर की जगह खेल रहे उरविग ने कई महत्वपूर्ण सेव किए।

दूसरी ओर बायर्न की टीम लंबे समय तक गेंद अपने पास रखने के बावजूद लय में नजर नहीं आई। हैरी केन ने पहले हाफ में एक हेडर बाहर मारा, जबकि लुइस डियान का शॉट स्टटगार्ट के गोलकीपर अलेक्जेंडर नुबेल ने रोक लिया।

दूसरे हाफ में बदला मैच का रुख

मैच का टर्निंग पॉइंट 55वें मिनट में आया। माइकल ओलिसे पर फाउल के बाद बायर्न ने तेजी से खेल शुरू किया। ओलिसे ने दाहिने छोर से शानदार क्रॉस दिया, जिस पर हैरी केन ने हेडर के जरिए गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद स्टेडियम में आतिशबाजी और धुएं के कारण मैच कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। खेल दोबारा शुरू होने के बाद बायर्न ने पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। 80वें मिनट में केन ने लुइस डियान के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए दूसरा गोल किया। इसके बाद इंजरी टाइम में स्टिलर के हेडबॉल के कारण मिले पेनाल्टी पर गोल कर उन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली।

जीत के बाद क्या बोले केन और कोम्पनी

मैच के बाद हैरी केन ने कहा, 'यह घेय बनाए रखने का मुकाबला था। पहला हाफ कठिन रहा, लेकिन हमने विपक्षी टीम को थका दिया। दूसरे हाफ में हमने शानदार प्रदर्शन किया और जीत के हकदार रहे। मुझे टीम पर बहुत गर्व है।' बायर्न के कोच विसेंट कोम्पनी ने कहा, 'हमने मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेला। यह लक्ष्य परफेक्ट कप फाइनल था।' वहीं स्टटगार्ट के कोच सेबास्टियन होएनेसे ने कहा, 'हार का दुख बहुत बड़ा है। 155 मिनट तक हमने पैसा ही खेल दिखाया जैसा जरूरी था। हम काफी करीब थे।'

व्यापार

9 साल का टूटा रिकॉर्ड, भारत में विदेशी कंपनियों की ताबड़तोड़ एंट्री

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों की एंट्री पिछले नौ सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे हैं। कुछ नए देश भी पहली बार इसमें शामिल हुए हैं। ईटी के विश्लेषण से इसका पता चलता है। उसने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के डेटा का विश्लेषण किया है। डेटा के मुताबिक, भारत में

रजिस्ट्रेशन के साथ ग्रोथ का नेतृत्व किया। वित्त वर्ष 2024-25 के एक रजिस्ट्रेशन से बढ़कर यह संख्या आठ हो गई। वहीं, दक्षिण कोरिया की संख्या चार से बढ़कर आठ हो गई। जापान की संख्या आठ से घटकर सात रह गई। पिछले वित्त वर्ष में भारत में विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बढ़कर नौ साल के सबसे ऊंचे स्तर 101 पर पहुंच गया। यह वित्त वर्ष 2024-25 के 57 रजिस्ट्रेशन से अधिक था। वित्त वर्ष 2016-17 में यह संख्या 103 थी। भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एक विदेशी कंपनी वह इकाई है जिसका निगमन विदेश में हुआ हो और जो भारत में अपना व्यवसाय खुद या किसी एजेंट के जरिये ऑपरेट करती है। दक्षिण अफ्रीका, घाना और उज्बेकिस्तान ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहली बार भारत में अपनी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया। सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के टॉप 10 स्रोतों में भी शामिल हैं। सामूहिक रूप से इन पांच देशों ने वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक) में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 62.4 प्रतिशत का योगदान दिया।

चीन का यह रहस्य नंबर

डेटा से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में चीन आठवें स्थान पर रहा, जहां से तीन रजिस्ट्रेशन हुए। जबकि पिछले तीन वर्षों में यह संख्या शून्य थी। औसतन, वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 के बीच भारत में चीनी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन घटकर सालाना दो रह गया। यह वित्त वर्ष 2018-20 की अवधि के दौरान सालाना नौ था।

काम करने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या में हालिया उछाल मुख्य रूप से सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और जर्मनी स्थित व्यवसायों से आया है। जापान के साथ मिलकर इन पांच देशों का वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कुल विदेशी कंपनी रजिस्ट्रेशन में आधे से ज्यादा हिस्सा रहा। इससे यह संख्या नौ साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। 13 नए रजिस्ट्रेशन के साथ सिंगापुर सबसे बड़ा कॉन्ट्रिब्यूटर रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में यह संख्या सात थी। इसके बाद अमेरिका 10 रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे पायदान पर रहा। ब्रिटेन ने नौ रजिस्ट्रेशन के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। जर्मनी ने आठ

दिग्गज का दावा- दो महीने से ज्यादा नहीं रहेगा पश्चिम एशिया संघर्ष का असर

नई दिल्ली, एजेंसी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने शनिवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर दो महीने से ज्यादा नहीं रहेगा। उद्योगों के बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर के दम पर भारत की ग्रोथ स्टेरी जारी रहेगी। जिंदल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) नागपुर के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। जिंदल ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उद्योग लंबी अवधि की योजनाओं पर फोकस करते हैं। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर अपनी उम्मीदों और निवेश पर पश्चिम एशिया संघर्ष के असर के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन ने संघर्ष को लेकर कहीं ये बातें सज्जन जिंदल ने कहा कि: पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक छोटा सा झटका है। हालांकि, हर कोई समझता है कि यह अस्थायी है। यह एक हफ्ते या एक महीने में, या अधिक-से-अधिक दो महीने में खत्म हो सकता है। जिंदल ने कहा कि उद्योग बहुत लंबी अवधि के लिए योजनाएं बनाते हैं, जो 20, 25 या 50 साल तक की हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'इसलिए, भारत की ग्रोथ का सफर जारी रहेगी। उद्योगों की ओर से भारी पूंजीगत खर्च किया जा रहा है। अब पूंजीगत खर्च की रफ्तार बढ़ रही है क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के बहीखाते बहुत मजबूत हैं।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी मुद्रा बचाने के आह्वान में उद्योगों की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर जिंदल ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' पहल ही विदेशी मुद्रा बचाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उन प्रमुख पहलों में से एक हैं जिन्हें जेएसडब्ल्यू ग्रुप तेल आयात कम करने और ई-परिवहन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के नजरिये के अनुरूप आगे बढ़ा रहा है। जिंदल ने बताया कि उनका ग्रुप नागपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सेल और बैटरी बनाने पर काम कर रहा है।

नाइट्रोजन उर्वरकों की आपूर्ति ठप होने के बाद इंसान के पेशाब की मांग, खाद संकट में किसानों ने तलाशे अनोखे विकल्प



नई दिल्ली, एजेंसी। इरान-अमेरिका तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरकों (खाद) की आपूर्ति ठप होने के बाद दुनिया भर के किसान फसलों को बचाने के लिए नए और अनोखे विकल्प तलाश रहे हैं। ब्युमबर्ग के मुताबिक रासायनिक खादों जैसे यूरिया की आसमान छूती कीमतों के बीच अब इंसानी पेशाब, मुर्गों की बीट और केंचुआ खाद जैसे प्राकृतिक और जैविक विकल्प अचानक भारी मांग में आ गए हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल यूरिया (एक प्रमुख नाइट्रोजन उर्वरक) का लगभग एक-तिहाई हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। हेमूज जलडमरूमध्य पर नाकेबंदी के चलते यूरिया की कीमतें कई सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। वहीं इस नाकेबंदी के कारण सप्लाई भी प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों ने

दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। **कितनी पहुंची कीमत** मिश्र का यूरिया युद्ध शुरू होने के बाद से 90 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 940 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि इस साल उर्वरक की कीमतों में करीब एक-तिहाई (30 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट गहराने का डर है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि इसके कारण 4.5 करोड़ अतिरिक्त लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर सकते हैं। कृत्रिम उर्वरकों ने एक सदी से वैश्विक खाद्य उत्पादन को संभाला हुआ है। ऐसा कोई सच्चा नहीं है कि आप इन्हें पूरी तरह हटा दें और पैदावार भी उतनी ही बनी रहे। इस संकट का कोई जादूई इलाज नहीं है। इस संकट ने उन

जैविक उत्पादों (बायो फर्टिलाइजर्स) को एक बड़ा मौका दे दिया है, जिन्हें किसान अब तक रासायनिक खादों से कमजोर मानते थे। इससे कई स्टार्टअप को भी ग्रोथ के मौके मिल सकते हैं। फ्रांस के स्टार्टअप टूपी ऑर्गेनिक्स ने स्कूलों और त्योहारों से इंसानी पेशाब इकट्ठा कर उसे एक ऐसे बैक्टीरिया फीड में बदलना शुरू किया है जो पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। फरवरी के बाद से कंपनी की बिक्री में 25 प्रतिशत का उछाल आया है। कंपनी के प्रतिनिधि फ्रांस्वा जेराड ने कहा कि युद्ध हमारे बिजनेस के लिए वादान साबित हुआ है। कच्चे माल के रूप में पेशाब हर जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

मुर्गों की बीट और केंचुए

मलेशिया की डेयरी कंपनी फार्म फ्रेश बीएचडी गाय-भैंसों के मलमूत्र को केंचुओं को खिलाती है, जिससे तैयार खाद घास को उपजाऊ बनाती है। अब वे इसमें मुर्गों की बीट भी मिला रहे हैं। ब्रिटेन के किसान जेम्स मिल्ल्य बताते हैं कि अब मुर्गों की बीट बेचने वालों के पास खरीदारों की लंबी लाइन लगी है।

सस्ते जैविक विकल्प

अमेरिकी कंपनी पिक्ट बायो ने अपने जैविक खादों के दाम 15 प्रतिशत तक घटा दिए हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद जकी हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।

संपादक :- सैयद जकी हैदर- हेड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कर्नोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक्रवी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM)

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।

नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)